बाबा रामदेव की राजनीतिक पार्टी : दिशा भाजपा तय करेगी

जब अन्ना हजारे के आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ गई। वैसे अन्ना ने नरेन्द्र मोदी का प्रशस्ति-गायन कर यह संकेत दे दिया था कि उनके वैचारिक रुझान क्या हैं और दरअसल, आगामी चुनावों में वे किस गठबंधन की जीत चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने सभी राजनीतिक नेताओं को भ्रष्ट बताना शुरू कर दिया तो आडवाणी जैसे पीएम-इन-वेटिंग रह चुके वरिष्ठ राजनेता नाराज़ हो गये। जब उन्होंने अपना क्षोभ प्रकट किया तो अन्ना ढीले पड़े। इधर, भाजपा की तरफ़ अन्ना का झुकाव देखते हुए कांग्रेस के कतिपय नेता कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह आदि उनका विरोध करने लगे। इस पर अन्ना ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि ये नेता उनकी छवि खराब करने पर तुले हुए हैं।

भाजपा को मिलने वाला नया साथी

सोनिया के सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी कि फ़िलवक्त अन्ना को साधे रखना जरूरी है, नहीं तो यह भाजपा के पाले में जायेगा और इससे कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम जनता में भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी आक्रोश है। इसके अलावा लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जो कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष संप्रग सरकार में दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रणव मुखर्जी बनाये गये। न्याय के धंधे से जुड़े और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व न्यायमंत्री शांतिभूषण सह अध्यक्ष बनाये गये जो वास्तव में भाजपा की ही संतान हैं, बेशक सक्रिय भाजपाई नहीं हैं। बाकी मनमाने तरीके से 'सिविल सोसाइटी' के प्रभावशाली और धनाढ्य लोग मसौदा कमेटी के सदस्य बन गये। इसमें भाजपा नेताओं को कहीं जगह नहीं मिली। अन्ना शासक वर्ग की मर्जी के अनुरूप उच्च न्यायपालिका, प्रधानमंत्री एवं उच्च नौकरशाही को प्रस्तावित लोकपाल के दायरे से बाहर रखने पर राजी हो गये। फ़िर भी कुछ बड़े पूर्व संपादकों एवं नेताओं ने अन्ना के तौर-तरीकों को लोकतांत्रिक आचरण के अनुरूप नहीं बताया। मायावती ने कहा कि कि इस कमेटी में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस कमेटी में किसी वर्ग अथवा समुदाय विशेष को प्रतिनिधित्व मिलने का सवाल ही नहीं था, सब कुछ अन्ना, उनके साथियों और कांग्रेसी नेताओं ने अपनी मन-मर्जी से किया। जंतर-मंतर पर तीन-चार दिनों का अन्ना ने जो ड्रामा किया, उसमें लाखों रुपये का खर्चा आया। यह खर्चा उद्योगपतियों और बड़े व्यवसायियों ने किया। इसके बाद अन्ना को हीरो बना दिया गया। पर अन्ना ने भ्रष्टाचार के विरोध में जो ड्रामा किया और जिसे मीडिया ने पूरे देश में दिखाते हुए जंतर-मंतर को तहरीर चौक तक बता दिया, उसका पूरा लाभ संसद में लोकपाल बिल पास करवा कर कांग्रेस लेगी। सवाल है कि भाजपा को क्या मिला जबकि भाजपा को अन्ना से काफ़ी उम्मीदें थीं।

यह देख कर कि अन्ना के इस ड्रामे से भाजपा को कोई चुनावी लाभ होने वाला नहीं है, पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है। अब वह योगगुरु रामदेव की लोकप्रिय छवि का सहारा लेना चाहती है। अन्ना से पहले बाबा रामदेव ने ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर-शोर से उछाला था और स्विस बैंकों में रखे गये काले धन को वापस लाने की बात कर जनता को आंदोलित करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि वे अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनायेंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहेंगे। लेकिन जब अन्ना ने इस सवाल पर भूख-हड़ताल शुरू कर दी तो प्रारंभ में बाबा रामदेव भौंचक रह गये और काफ़ी सोच-विचार के पश्चात् बेमन से अन्ना को समर्थन देने जंतर-मंतर पहुंचे। लेकिन बाद में वे फ़िर कभी वहां नज़र नहीं आये।

इसकी वजह यह है कि बाबा रामदेव अति महत्त्वाकांक्षी हैं और उनका मकसद एक राजनीतिक दल खड़ा कर चुनाव लड़ना-लड़वाना है। उनका कहना है कि राजनीतिक दल बनाने के लिए पूरे देश में उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार कर दिया है। बाबा गेरुआ वस्त्रधारी हैं। भारत का चुनावी इतिहास बताता है कि इस देश की जनता ने किसी गेरुआ वस्त्रधारी को राजनीतिक नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया। आज़ादी मिलने के बाद कुछ संतों ने राजनीतिक पार्टी बना कर देश की राजनीति में दखलंदाजी करनी चाही थी, पर उनका बुरा हश्र हुआ। बाबा ने योग को एक उद्योग का रूप दिया है, आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री अमेरिका तक में खोली है। पर इनके बारे में कहा जाता है कि अपनी फैक्ट्रियों में ये मज़दूरों का काफ़ी शोषण करते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी भी उन्हें नहीं देते। इसके अलावा श्रम कानूनों की पालना भी इनकी दवा फैक्ट्रियों में नहीं होती। जो भी हो, पिछले एक दशक के दौरान बाबा ने योग और दवा उद्योग के माध्यम से काफ़ी पैसा बनाया है। कहा जाता है कि इन्होंने कतिपय टीवी चैनलों पर भी अपना स्वामित्व स्थापित किया है। दरअसल, आधुनिक प्रचार तंत्र के चमत्कारिक प्रभाव को बाबा ने शुरू में ही समझ लिया था और तभी इन्होंने सीडी और टीवी आदि के माध्यम से अपना जबरदस्त प्रचार किया और मध्य वर्ग में अपना अच्छा-खासा प्रभाव कायम कर लिया। बाबा के पास जब काफ़ी पैसा आ गया तो ये समाज के उच्च तबके और शासक वर्ग के करीब भी आये। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर तक बना दिया। इन्होंने अपनी पैठ फ़िल्मी दुनिया तक बनाई और बड़े ही व्यावसायिक ढंग से योग और भोग को जोड़ा।

शीघ्र ही बाबा इस देश के बड़े-बड़े नेताओं के साथ मंचों पर आसीन नज़र आने लगे। शुरू में इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशी दवा निर्माता कंपनियों और कोल्ड ड्रिंक आदि का जबरदस्त विरोध किया था, इसलिए इन मुद्दों पर संघर्ष करने वाले लोगों के मन में भी बाबा के भगवे चोले के बावजूद एक सहानुभूति का भाव नज़र आने लगा था, पर बाबा ने जल्दी ही अपना हिंदूवादी सांप्रदायिक चेहरा दिखा ही दिया।

अब ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि बाबा जो राजनीतिक पार्टी बनायेंगे, उससे भाजपा और संघ परिवार से दूर किये जा चुके और राजनीतिक वनवास भोग रहे गोविंदाचार्य को जोड़ेंगे। एक ज़माने में गोविंदाचार्य भाजपा के थिंक टैंक माने जाते थे। एक सफल संगठनकर्ता के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान थी। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बना कर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए भेजा था। गोविंदाचार्य भाजपा में संगठन को मजबूत बनाने का काम संघ की अपेक्षाओं के अनुरूप कर रहे थे, पर इसी बीच 'सेक्सी संन्यासिन' कही जाने वाली और 'खिलौनों' से खेलने वाली उमा भारती के गेसुओं में उलझ गये। इसके बाद अपने एक बयान में इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी को 'मुखौटा' कह दिया। वाजपेयी को उदार हिंदूवाद का प्रवक्ता कहा जाता था। उन्हें मुखौटा कहा जाना इसी संदर्भ में था। बात तो गोविंदाचार्य ने सही कही थी, पर इसका खामियाजा इन्हें राजनीतिक वनवास के रूप में भुगतना पड़ रहा है, यद्यपि बाद में इन्होंने वाजपेयी को 'मुकुट' तक कहा, पर भाजपा से किनारे कर दिये गये। लेकिन गोविंदाचार्य ने अपनी सामाजिक सक्रियता नहीं छोड़ी। इन्होंने 'स्वदेशी' की पुनरुत्थानवादी अवधारणा को पेश किया और मल्टीनेशनल्स के विरोध का मुद्दा सामने रखा। यद्यपि इनका स्वदेशी आंदोलन चल नहीं पाया, पर अभी भी ये राष्ट्रवादी मोर्चा बना कर सक्रिय हैं जिसमें कहा जाता है कि संघ और भाजपा के कुछ लोग भी इनके साथ हैं।

बाबा इन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि संगठन का काम करने में ये माहिर हैं। इनके साथ दिक्कत धन की है। पर बाबा के पास धन की कमी नहीं है। स्वदेशी को लेकर दोनों के विचार भी मिलते हैं। इसलिए बाबा गोविंदाचार्य को अपने साथ जोड़ कर एक सांप्रदायिक संगठन का निर्माण करना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बवाल खड़ा कर सत्ता में साझेदारी कर सके। लाख प्रयासों के बावजूद उमा भारती की भाजपा में पुनर्वापसी नहीं हुई, इसलिए पूरी संभावना है कि वह भी गोविंदाचार्य के साथ बाबा की राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जायें। उनकी अपनी पार्टी तो टूट-बिखर चुकी है।

बाबा इस बात को भली-भांति जानते हैं कि अन्ना का उद्देश्य सिर्फ़ लोकपाल बिल भर पास करवाना है। उसके बाद वे महाराष्ट्र के अपने गांव में जाकर बैठ जायेंगे। पर उनका उद्देश्य राजनीति करना है और वे भ्रष्टाचार के साथ काले धन की वापसी का मुद्दा उठा कर निम्न मध्य वर्ग के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। इधर असांजे का विकीलीक्स भी इस मुद्दे को उठा रहा है। इससे बाबा को खाद-पानी मिलेगा। वैसे लोकसभा चुनाव में अभी देर है, पर कांग्रेस का बाजा पूरी तरह बज चुका है। वर्तमान स्थितियों में किसी अवसरवादी तीसरे मोर्चे की संभावना नहीं है। कांग्रेस के गठबंधन के बाद भाजपा का गठबंधन सत्ता में आने के लिए बेकरार है। ऐसे में बाबा अगर सचमुच कोई राजनीतिक संगठन बनाते हैं तो उसकी दिशा भाजपा ही तय करेगी।

- जॉन

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इस अंक में प्रकाशित सभी समाचार एवं लेख पसंद आये। विशेषकर अन्ना के आंदोलन पर जो लेख लिखा गया है, वह काफ़ी पसंद आया। उसमें भी आपने इंकलाबी मज़दूर केंद्र की टिप्पणी कार्टून के साथ जो छापी है, वह एकदम मेरे विचारों के अनुकूल है। कन्या भ्रूण हत्या पर जो समाचार आपने छापा है, वह दिखाता है कि हमारा प्रशासन तंत्र कितना भ्रष्ट हो गया है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र डीसी और डीसी की मूर्खता से संबंधित छोटे-छोटे समाचार जो आपने छापे हैं, वह प्रशासन तंत्र की विफलता को दिखाने के लिए काफ़ी हैं। पेयजल की समस्या और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित रिपोर्ट भी सच्चाई को सामने लाती है। मज़दूर मोर्चा एक ऐसा अख़बार है जो बराबर आम जनता के हित में ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहा है। इसके लिए संपादक एवं प्रकाशक बधाई के पात्र हैं।

- राजेन्द्र सिंह
सेक्टर-15ए, फ़रीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का अंक मिला। कन्या भ्रूण हत्या पर जो समाचार आपने प्रकाशित किया है, वह राज्य के प्रशासन में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले भ्रष्टाचार को दिखाता है। ऐसी स्थिति में भ्रूण हत्याओं को रोक पाना असंभव है। यही कारण है कि हरियाणा के युवाओं को अब शादी योग्य लड़कियां राज्य में नहीं मिल रही हैं और वे दूसरे राज्यों से दलालों के माध्यम से लड़कियों को खरीद कर लाने पर मजबूर हो रहे हैं। कई बार तो दलाल उन्हें ठग लेते हैं और पेशेवर लड़कियों को उनके यहां ला कर बिठा देते हैं जो थोड़े ही दिनों में उनका सारा माल लेकर चंपत हो जाती हैं। अन्ना के आंदोलन पर मनोज का लेख बहुत ही अच्छा लगा। इस लेख में असलियत सामने लाई गई है। इसी तरह पानी की समस्या और राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर जो रिपोर्ट लिखी गई है, वह तथ्यात्मक होने के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण सवालों को उठाती है। कृपया इस अख़बार में मज़दूरों की समस्याओं को सामने लाने के लिए एक अलग पृष्ठ दें।

नगेन्द्र
आजाद नगर, सेक्टर-24, फ़रीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। कन्या भ्रूण हत्या पर प्रकाशित ख़बर पढ़ कर लगा कि पैसे के लिए अधिकारी वर्ग मानवता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। चूंकि मैं स्वयं एक चिकित्सक हूं, इसलिए इस ख़बर ने मेरी संवेदना को झकझोर कर रख दिया। ऐसे मानवता के दुश्मन डॉक्टरों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पर सवाल है, कार्यवाही करेगा कौन? पूरा प्रशासन तंत्र सड़ गया है। हुड्डा जैसे मुख्यमंत्री भ्रष्ट प्रशासकों को जम कर प्रोत्साहन दे रहे हैं और संभवत: उनके द्वारा ली जाने वाली मंथलियों में अपना हिस्सा भी बंटा रहे हैं। अन्य सामग्री भी ठीक-ठाक है। पर अन्ना के आंदोलन की आलोचना अच्छी नहीं लगी। अन्ना भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, इसे हमें समझना चाहिए। अब सत्ता में बैठे लोग अन्ना का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उनका विरोध शुरू करें। मीडिया ने लगातार अन्ना के अभियान का समर्थन किया है। पर आप और इंकलाबी मज़दूर केंद्र उनका विरोध कर रहा है। यह बात समझ में नहीं आई। पानी और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा पर जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, सोलहो आने सच है। उम्मीद है, यह अख़बार अगले अंकों में और भी ज्वलंत विषयों पर अपनी धारदार लेखनी से सोये हुए समाज को जागृत करने का प्रयास करेगा।

डॉ. हेमराज ढींगड़ा
2 डी 44, एनआईटी, फ़रीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का मैं नियमित पाठक हूं। इस बार का अंक काफ़ी अच्छा है। कन्या भ्रूण हत्या पर जो समाचार आपने प्रकाशित किया है, उससे पता चलता है कि राज्य में प्रशासनिक भ्रष्टाचार किस हद तक जड़ें जमाये बैठा है। दरअसल, यह स्थिति सिर्फ़ हरियाणा की ही नहीं है, लगभग सभी राज्यों में मानवता के दुश्मन यह व्यापार चला रहे हैं। बिहार के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में यह धंधा पूरे जोर-शोर से चल रहा है और कोई इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अंक में प्रकाशित लेख काफ़ी स्तरीय होते हैं। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर मनोज का लेख काफ़ी अच्छा लगा। खास कर इंकलाबी मज़दूर केंद्र की टिप्पणी कार्टून के साथ छप कर काफ़ी धारदार हो गई है। जनता को अन्ना जैसे समाज-सुधारकों के छलावे में नहीं पड़ना चाहिए। पेयजल की समस्या हर जगह है। हर जगह पानी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो आपने लिखा है, वह तथ्यात्मक है, पर आज लगभग सभी राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल है। बिहार में तो स्थिति नारकीय है। आपसे निवेदन है कि साहित्य और सांस्कृतिक समाचारों के लिए भी स्थान निर्धारित करें तथा जरूरी पुस्तकों की समीक्षा अथवा उनका परिचय प्रस्तुत करें। मज़दूरों की दशा एवं उनके आंदोलन की दिशा पर हर अंक में सामग्री होनी चाहिए।

- सतीश चंद्र झा, गांधी नगर, डेहरी ऑन-सोन, बिहार